www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 15 | जौनपुर, शनिवार, 29 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

## संक्षिप्त खबरें

### देश के लिए सबसे बड़ा संकट है सत्तारूढ़ दल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इटावा के सैफई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है और सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद–बीज न मिलने और मीडिया पर पाबंदियां लगाए जाने का भी मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को देश के सामने ''सबसे बड़ा संकट'' करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे अखिलेश ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''देश में केवल एक ही संकट है और वह भाजपा है। भाजपा खुद सबसे बड़ा संकट है। भाजपा जाएगी तो संकट भी चला जाएगा।'' उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास ''नफरत फैलाने'' के अलावा कोई काम नहीं है और उन्होंने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की विरासत को ''बेचने'' का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के गठन के समय पार्टी ने खुद को समाजवादी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश में जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाई थी, लेकिन अब उसने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (जेपीएनआईसी) को ''बेच'' दिया है। सपा प्रमुख ने कटाक्ष करते हुए कहा, ''भाजपा को कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, वरना भाजपा खुद को बेच देती।'' महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की कीमतें बढ़ने दे रही है। उन्होंने कहा, ''चीनी की बात करें तो चीनी महंगी हो गई है। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है। मिलावट को लेकर कानून है और कानूनी तौर पर आप मिलावट नहीं कर सकते।

## नेपाल के हालात पर रखें नजर, बाढ़ प्रभावित लोगों को न हो दिक्कत - सीएम योगी

गोरखपुर, (संवाददाता)। नेपाल में बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ–साथ जिले में भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। जिन गांवों में पानी पहुंचा है, वहां प्रभावित लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों की योजनाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि शहर में जलभराव की स्थिति न बनने पाए। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में पहले से जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं। राहत और बचाव से जुड़े संसाधनों को भी तैयार रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में चल रही विकास परियोजनाओं की एक–एक कर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति और तय समयसीमा की जानकारी ली। कहा कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाई जाए और अधिकारी नियमित निगरानी करें। बैठक में विरासत गलियारा, गोड़धोइया नाला, असुरन–चारफाटक फोरलेन, एचएन सिंह चौराहा–गोरखनाथ मार्ग चौड़ीकरण, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, वेटरनरी कॉलेज और एकीकृत मंडलीय कार्यालय समेत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। बिजली निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में लाइन लॉस अधिक है, वहां विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने लोगों को समय से बिजली बिल जमा करने के लिए जागरूक करने और लाइन लॉस हर हाल में कम करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

## नितिन नवीन की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और पूरे देश में युवाओं के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करना था। इस बैठक में हर राज्य से दो–तीन नेता शामिल हुए। बैठक में युवाओं के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों की पहचान करने और युवा पीढ़ी के साथ बातचीत और संवाद को बेहतर बनाने की रणनीतियां तैयार करने पर ध्यान दिया गया। इसमें

ठश्रच के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, गुरु प्रकाश पासवान, हेमांग जोशी, योगेंद्र चंदोलिया और राजू बिस्टा शामिल थे। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में मौजूद थीं। इन चर्चाओं का मकसद युवाओं तक बीजेपी की पहुँच और उनसे जुड़ाव बढ़ाने के लिए एक तालमेल वाला तरीका तैयार करना था। इससे युवाओं की उम्मीदों और भारत के विकास में उनकी भूमिका से जुड़ने पर पार्टी के बड़े फोकस का पता चलता है। इससे पहले, 27 अगस्त को अहमदाबाद में श्फार्मिन्नोवा अवार्ड्स सेरेमनी–2026 में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के भविष्य के लिए युवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास फोकस पर जोर दिया। शाह ने श्आजादी का अमृत महोत्सवश समारोह के दौरान मोदी द्वारा बताए गए तीन मुख्य लक्ष्यों का जिक्र किया, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न है शाह ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी के लिए एक लक्ष्य तय किया है।

## छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को होगा सर्वाधिक नुकसान – भूपेश बघेल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर राज्य में युसीसीलागू होता है, तो आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। पत्रकारों से बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने युसीसी और इसके

संभावित सामाजिक असर को लेकर अपनी पुरानी चिंताओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था, तब भी मैंने कहा था कि अगर युसीसी कानून बनता है, तो आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को, युसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई उच्च–स्तरीय समिति ने क्षेत्रीय नेताओं, संस्थाओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए राज्यव्यापी आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर दिया है। शत्रुघ्न सिंह ने इन इंटरैक्टिव सत्रों की प्रक्रिया और मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक हाई–लेवल कमिटी बनाई है और यह कमिटी लोगों की राय जानने के लिए राज्य के अलग–अलग इलाकों का दौरा कर रही है।

## एससीओ क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाना लक्ष्य, मध्य एशिया यात्रा शुरू – पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अगस्त से उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना हुए हैं, जहां वह बिश्केक में आयोजित 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस मंच के जरिए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने तथा आतंकवाद, अलगाववाद व उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा के दौरान ताशकंद में द्विपक्षीय साझेदारी और व्यापार–ऊर्जा सहयोग को विस्तार देने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लिए भारत के उस दृष्टिकोण को आगे

बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, जो सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह क्षेत्र को आतंकवाद के अभिशाप से मुक्त बनाने के लिए संगठन के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी यह यात्रा मध्य एशिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी तथा इस क्षेत्र के साथ भारत के सभ्यतागत संबंधों को और गहरा करेगी। प्रधानमंत्री का दोनों देशों का दौरा 29 अगस्त से शुरु होकर एक सितंबर को समाप्त होगा। मोदी ने यात्रा से पहले जारी बयान में कहा कि यह दौरा शांति, स्थिरता और समृद्धि के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसे मूल्य हैं, जो दुनिया के साथ भारत के संबंधों के केंद्र में रहे हैं। मोदी ने कहा, ''भारत 2017 से एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहा है। मैं सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने तथा सदस्य देशों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्र के निर्माण के लिए काम करने को उत्सुक हूं, जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के अभिशाप से मुक्त हो। ये चुनौतियां हमारे पड़ोस के साथ–साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी शांति और स्थिरता के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं।

## रक्षा निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने किए बड़े सुधार

लखनऊ, (संवाददाता)। सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने रक्षा निर्यात मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सरल बनाने के लिए व्यापक सुधार किये हैं, जिसके तहत संवेदनशील देशों के लिए ''उचित सुरक्षा उपाय'' बनाए रखते हुए अधिकांश गंतव्यों के लिए गैर–घातक रक्षा सामग्री के निर्यात के लिए हितधारकों के परामर्श को 'समाप्त' कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय निविदाओं और प्रदर्शनियों के लिए सभी सामग्रियों के निर्यात के लिए भी हितधारकों के परामर्श को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का अधिक तेजी से लाभ उठाने में सक्षम होंगी। बयान के अनुसार, मंत्रालय

के रक्षा उत्पादन विभाग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को एक विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी और भरोसेमंद वैश्विक रक्षा विनिर्माण तथा निर्यात भागीदार बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा निर्यात एसओपी और खुली सामान्य निर्यात लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के लिए सुधारों का एक व्यापक 'सेट' शुरू किया है, जिससे 'मेक–इन–इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। रक्षा निर्यात एसओपी को आसान बनाने के बारे में कहा गया, है, ''ज्यादातर जगहों पर गैर–घातक रक्षा सामग्रियों के निर्यात के लिए हितधारकों से सलाह–मशविरा करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, जबकि संवेदनशील देशों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय बनाए रखे गए हैं।'' मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इन सुधारों का उद्देश्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंच बनाना और भारतीय रक्षा कंपनियों को वैश्विक व्यापारिक अवसरों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाना है, जबकि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। रक्षा निर्यात एसओपी के सरलीकरण पर इसने कहा, ''अधिकांश देशों को गैर–घातक रक्षा सामग्री के निर्यात के लिए हितधारकों के परामर्श को समाप्त कर दिया गया है।

## नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के लोगों का एक समूह सुरक्षित भारत लौटा, सीएमओ ने दी जानकारी

नेपाल, (एजेंसी)। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे प्रदेश के लोगों का एक समूह सुरक्षित भारत लौट आया है और अब अपने राज्य वापस आ रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुश्किल हालात में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों को अधिकारियों की कोशिशों के बाद वहां से निकाला गया। सुरक्षित भारत पहुंचने के बाद, उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और तुरंत मदद और सहयोग के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। सीएमओ के अनुसार, नागरिकों ने महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी सुरक्षित वापसी के लिए तेजी से कार्रवाई, तालमेल और लगातार कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया। वर्चुअल बातचीत के दौरान,

उन्होंने नेपाल में फंसे रहने के बाद भारत वापस आने पर राहत की सांस ली। सुरक्षित वापसी के बाद फंसे हुए नागरिकों से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की कोशिशों से ही उन्हें समय पर वहां से निकाला जा सका और वे वापस आ पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित नागरिकों तक तुरंत मदद पहुंचे और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। महाराष्ट्र सीएमओ देर रात एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि नागरिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यालय ने बचाव अभियान में शामिल राज्य सरकार और अधिकारियों के बीच तालमेल पर भी जोर दिया। इससे पहले, 28 अगस्त को सीएमओ ने बताया था ।

## नेपाल आपदा के बीच डब्ल्यूएचओ ने बढ़ाया मदद का दायरा, 150,000 डॉलर की सहायता राशि जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) नेपाल में आई बाढ़ को लेकर अपनी मदद का दायरा बढ़ा रहा है, जिसके तहत तत्काल 150,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि जारी की गई है। आवश्यकता आकलन जारी रहने के साथ–साथ अतिरिक्त संसाधन जारी किए जाने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि आपदा शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर, डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन आपूर्ति भेजी, जिसमें अंतर–एजेंसी आपातकालीन

स्वास्थ्य आपूर्ति भी शामिल थी, जो लगभग 10,000 लोगों को 3 महीने तक आवश्यक सामग्री प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, इसमें टेंट, 10,000 मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारी तत्काल प्राथमिकता प्रभावित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करना और बाधित स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएचओ नेपाली सरकार के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए साझेदारों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय, निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित समुदायों के सामने भारी चुनौतियां हैं, ऐसे में सभी साझेदारों का निरंतर समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। डब्ल्यूएचओ इस कठिन समय में नेपाल सरकार और जनता के साथ खड़ा है और देश की बदलती जरूरतों के आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 10 टन से अधिक मानवीय सहायता सामग्री और डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों की टीम लेकर तीसरी विशेष उड़ान नई दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुई है।

## भूमि विवाद बन रहा खूनी संघर्ष व हत्या की वजह पुलिस-राजस्व तंत्र के कार्यशैली पर उठ रहा प्रश्न चिन्ह

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले में हत्या,मारपीट और कब्जे के विवादों पर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद इधर हो रही आपराधिक वारदातों मे कमी होती।भूमि विवादों को समय रहते निपटाने में पुलिस और राजस्व विभाग की कथित लापरवाही अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है।देखा जाये तो आबादी के जमीन,रास्ते और कब्जे से शुरु होने वाला विवाद कई बार मारपीट से बढ़कर हत्या तक पहुंच जाता है।देखा जाये तो विवाद की शुरुआती सूचना मिलने के बाद भी यदि संबंधित थानाध्यक्ष,लेखपाल,कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम स्तर गंभीरता से निपटाने का काम करे तो इस तरह की घटना ही न घटे।हाल ही में पूराकलंदर, महाराज गंज, रौनाही, कुमारगंज सहित अन्य थाना क्षेत्रों में भूमि विवाद से जुड़ी आपराधिक घटनाओ ने इस पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।देखा जाये तो यदि राजस्व संबंधी विवाद का समय रहते निष्पक्ष और प्रभावी समाधान हो जाता तथा पुलिस स्तर पर दोनों पक्षों को पाबंद कर आवश्यक कार्रवाई की जाती, तो संभव है कि विवाद खूनी रूप न लेता।विवादित जमीन की पैमाइश, रास्ते, कब्जे, सीमांकन अथवा बंटवारे जैसे मामले अक्सर लंबे समय तक लंबित रहते हैं।लोगो का मानना है कि विवादित पक्ष बार–बार थाना और तहसील के चक्कर लगाते हैं।ऐसे मामलों में यदि संबंधित लेखपाल और कानूनगो मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट समय पर दें तथा तहसीलदार और एसडीएम स्तर से प्रभावी निर्णय हो,तो विवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है।वही पुलिस के सामने जब भूमि विवाद से जुड़ी शिकायत पहुंचती है तो केवल शांति भंग की कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय विवाद की संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी है।दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति में समय रहते निरोधात्मक कार्रवाई और लगातार निगरानी कई बड़ी घटनाओं को रोक सकती है।जिले में थाना दिवस और तहसील दिवस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की शिकायतें सुनने की व्यवस्था है,बावजूद यदि एक ही भूमि विवाद कई बार पुलिस व राजस्व अधिकारियों के सामने पहुंच रहा है और उसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो यह व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। शिकायत के निस्तारण के साथ यह देखना भी जरूरी है कि विवाद दोबारा न भड़के और दोनों पक्ष कानून हाथ में न लें।पुलिस के सामने लूट, हत्या, चोरी और छिनैती की चुनौती घटनाओं पर अंकुश लगाने की भी चुनौती है।वही ऐसे मामलों में बीट पुलिसिंग,संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है।यदि किसी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो उनकी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करना भी आवश्यक है। भूमि विवाद से शुरू होकर हत्या तक पहुंचने वाली घटनाओं में केवल पुलिस को जिम्मेदार ठहराना भी पर्याप्त नहीं है।कई मामलों में राजस्व स्तर पर लंबित सीमांकन,पैमाइश या कब्जे का विवाद, फिर पुलिस तक पहुंचता है और अंततः कानून–व्यवस्था की समस्या बन जाता है।इसलिए पुलिस और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।सवाल यह उठ रहा है जब किसी भूमि विवाद की जानकारी पहले से पुलिस और राजस्व अधिकारियों को होती है,तो उसे गंभीर अपराध में बदलने से पहले रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?अगर संबंधित लेखपाल–कानूनगो से लेकर तहसीलदार,एसडीएम और थानाध्यक्ष तक संवेदनशील मामलों की नियमित समीक्षा करें और शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, तो निश्चित रूप से कई विवादों को खूनी संघर्ष में बदलने से रोका जा सकता है।

# संपादकीय

## ट्रंप काल में कई बातें उजागर

अडानी धन की ताकत से वे अमेरिका में भी बरी हो गए हैं। मगर इस क्रम में यह भी साफ हुआ है कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है और उस पर धन का कितना प्रभाव है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस ने अडानी समूह के खिलाफ घूस देने और धोखाधड़ी के आपराधिक मुकदमे को खारिज करने पर यह कहते हुए सहमति दे दी कि श्संघीय अभियोजकों के निर्णय की समीक्षा करने का जज के पास सीमित अधिकारश्च है। लेकिन उन्होंने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग के इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा– श्अभियोग खारिज करने के निर्णय में बरती गई अनियमितताएं चिंताजनक हैं।ष उन्होंने दो टूक कहा कि न्याय विभाग ने सामान्य से हटकर अलग प्रक्रिया अपनाई। जज ने खासकर न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैक्कॉटर की आलोचना कड़ी की है। कहा– मैक्कॉटर ने विभिन्न संघीय कार्यालयों के अनगिनत अधिकारियों और विशेषज्ञों की पेशेवर राय को नजरअंदाज कर दिया। जज ने बेलाग इस पर रोशनी डाली कि न्याय विभाग ने यह फैसला अडानी के वकीलों के साथ मिलकर लिया, जबकि अमेरिकी जांच एजेंसियों– एफबीआई और एसईसी, इस केस को दर्ज करने वाले अभियोजकों तथा अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की कोई सलाह नहीं ली गई। जज ने इसे श्अत्यंत असामान्यष बताया है। इससे पहले जब न्याय विभाग ने केस वापस लेने का शुरुआती अनुरोध भेजा, तो जज ने उसे श्कमजोर, सतही और अस्पष्टष तर्कों पर आधारित बताया था। तब कोर्ट ने न्याय विभाग से मामले को खारिज करने के ठोस कारण मांगे थे। अब अंतिम फैसले में न्यायाधीश ने जो कहा है, उससे साफ है कि न्याय विभाग उन्हें संतोषजनक जवाब भेजने में नाकाम रहा। उसने स्पष्ट नहीं किया कि अडानी समूह के किन शर्तों पर राजी होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने उपरोक्त फैसला लिया। इसके पहले अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा दर्ज कराए गए के मुकदमे में गौतम अडानी 60 लाख और उनके भतीजे सागर एक करोड़ 20 लाख डॉलर का भुगतान करने पर राजी हुए थे। इस तरह धन की ताकत से वे अमेरिका में भी बरी हो गए हैं। मगर इस क्रम में अमेरिकी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है और उस पर धन का कितना प्रभाव है, यह साफ हुआ है। ट्रंप काल में ऐसी कई बातें उजागर हो रही हैं, जो जिन पर पहले परदा पड़ा रहता था।

# विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

ललित

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल–क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है–ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा–व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024–25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है–फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024–25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल–शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023–24 के 1,10,971 से घटकर 2024–25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014–15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024–25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार–चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है। इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा–व्यवस्था

के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल–इन सबको अलग–अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है। यहां एक कठोर लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार होना चाहिए–क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित अथवा अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब नीति बनाने वाले परिवार स्वयं उसी व्यवस्था का अनुभव करेंगे, तब शायद स्कूल की टूटी खिड़की, बंद शौचालय, शिक्षक की कमी और खराब मिड–डे–मील केवल फाइल की टिप्पणी नहीं रहेंगे, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएंगे। शिक्षा को केवल मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म या मुफ्त पुस्तकों की योजनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता।

# जातिगत जनगणना सम्बन्धी कांग्रेस–भाजपा के सियासी दांव–पेचों को यूँ जानिए

कमलेश

जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ मौजूदा हमला केवल "जाति गिनी जाए या नहीं" का सवाल नहीं है, बल्कि असली

लड़ाई अब डेटा की विश्वसनीयता, सामाजिक न्याय की राजनीति और उससे बनने वाले नए राजनीतिक समीकरण की है। यही वजह है कि अगस्त 2026 में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा जाति–जनगणना पद्धति पर आपत्ति जताई है। इसलिए जातिगत जनगणना सम्बन्धी कांग्रेस–भाजपा के सियासी दांव–पेचों को ऐसे जानिए। कांग्रेस का तर्क है कि यदि जातियों के नाम दर्ज करने के लिए स्पष्ट, पूर्व–निर्धारित सूचीध्कोडिंग व्यवस्था नहीं होगी, तो अलग–अलग नाम, वर्तनी और उपजातियों के कारण आंकड़े अविश्वसनीय हो सकते हैं। इसलिए उसने इसे दुरुस्त करने की मांग उठाई, ताकि जातिगत जनगणना सही तरह से हो सके। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस ने 2011 में जिस जातिगत जनगणना के आंकड़ों को छुपाने में ही अपनी भलाई समझी थी, उसी ने अब भाजपा पर दबाव बना दिया कि जातिगत जनगणना करवाओ और भाजपा को यह बात माननी पड़ी, क्योंकि लालू–नीतीश की समझदारी के सामने भाजपा नेतृत्व विवश हो गया। चाहे लालू प्रसाद हों या नीतीश कुमार, इन्होंने सबके लिए कम और अपनी जातियों और उससे पहले दोस्तों के लिए बहुत कुछ सोचा। इसलिए डेढ़–दो दशक बाद ही सही, लेकिन दोनों को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। यही वजह है कि जब केंद्र सरकार ने पिछले साल जब जाति जनगणना कराने की तारीखों का ऐलान किया, तभी स्पष्ट था कि यह काम चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। देश की राजनीति में जाति हमेशा अहम रही है, लेकिन इसे निश्चित करना उतना ही मुश्किल। अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू ही हुई है और जाति की गणना दूसरे चरण में की जाएगी, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जाति जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों का कॉलम नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आंकड़े जुटाने के सरकारी तरीकों पर भी अंगुली उठाई और कहा कि जाति जनगणना में जाति का कॉलम खुला रखकर एक सवाल छोड़ दिया गया है, यानी यहां सभी को अपनी जाति खुद लिखनी है। अब चूंकि देश के विभिन्न हिस्सों में एक ही जाति को अलग–अलग नामों से जाना जाता है, तो आंकड़े उलझे हुए मिल सकते हैं। इससे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होगा। वाकई, इस आशंका को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि 2011 की सामाजिक–आर्थिक और जातिगत जनगणना में भी इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया था। तब 46 लाख से ज्यादा जातियां, उपजातियां, उपनाम दर्ज हो गए थे। इन आंकड़ों में इतनी विसंगति थी कि सरकार ने इनको जारी ही नहीं किया। इसलिए कांग्रेस का ताजा सुझाव है कि लोगों पर छोड़ने के बजाय जातियों की पहले से एक तय सूचीधलिस्ट होनी चाहिए। इससे एक जाति एक ही नाम से दर्ज होगी और स्पेलिंग की भी गलती नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं है कि देश में कितनी जातियां और उनकी कितनी आबादी है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि अलग–अलग सामाजिक समूहों की वास्तविक स्थिति क्या है। अबतक असमानता दूर करने के लिए लागू की गई नीतियां कितनी कारगर रहीं और आगे उनमें किन बदलावों की दरकार है, इसकी सही तस्वीर जानने के लिए आंकड़ों की शुद्धता मायने रखती है। इसी से शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। और अगर किसी तरह का सवाल या संदेह है, तो उसे पहले ही दूर कर लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी सुझाव आते हैं उन पर विचार–विमर्श करने में हर्ज नहीं है। साथ ही, यह भी स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है कि जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। चूंकि जाति जनगणना का देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ने वाला है। इसलिए प्रक्रिया पूरी तरह भरोसेमंद और सवालों के परे होनी चाहिए। अब आइए सबसे पहले इस जातिगत जनगणना के लाभ–हानि को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, नीति पहली बार वास्तविक सामाजिक आंकड़ों पर टिक सकती है। किस जाति की कितनी आबादी है, उसकी शिक्षा, रोजगार, आय और सरकारी योजनाओं तक पहुंच कैसी हैकृइसका बेहतर आधार मिल सकता है। इससे कल्याणकारी योजनाओं को अधिक लक्षित किया जा सकता है। दूसरा, आरक्षण पर बहस अधिक तथ्य आधारित हो सकती है। अभी अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या को लेकर अलग–अलग अनुमान हैं। इसलिए विश्वसनीय आंकड़े मिलने पर प्रतिनिधित्व और आरक्षण की समीक्षा का आधार मजबूत हो सकता है। तीसरा, "जिसकी जितनी संख्या..." राजनीति को आंकड़ों की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस लंबे समय से इसी तर्क को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आंकड़े आने के बाद यह नारा भी चुनौती में बदल सकता हैकृक्योंकि हर जाति अपने वास्तविक सामाजिक–आर्थिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व का हिसाब मांगेगी। पहली बड़ी समस्या जाति की पहचान को स्थायी राजनीतिक पहचान बना देने का खतरा है। अगर आंकड़ों का इस्तेमाल केवल चुनावी टिकट, आरक्षण और वोट–बैंक की राजनीति के लिए हुआ तो सामाजिक विभाजन और तीखा हो सकता है। दूसरी बड़ी समस्या डेटा की गुणवत्ता है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैंय एक ही समुदाय के अलग–अलग स्थानीय नाम और वर्तनी हैं। 2011 के सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आंकड़ों में ऐसी तकनीकी समस्याओं का हवाला सरकार पहले भी दे चुकी है। इसलिए कांग्रेस की मौजूदा आपत्ति पूरी तरह खारिज करने लायक भी नहीं है। सवाल यह है कि जाति गिनने के बाद उसे सही ढंग से वर्गीकृत और सत्यापित कैसे किया जाएगा। यहीं इस विवाद का राजनीतिक अर्थ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि 2024 के बाद कांग्रेस ने "जाति जनगणना. सामाजिक न्याय. प्रतिनिधित्व" को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। भाजपा ने अप्रैल 2025 में आगामी जनगणना में जाति को शामिल करने का निर्णय लिया और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। अर्थात कांग्रेस की पुरानी मांग को स्वीकार करके भाजपा ने कांग्रेस का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अपने हाथ में ले लिया। इसलिए अब कांग्रेस की रणनीति है।

# धान की फसल में कीट प्रकोप से बचाव के लिए किसान रहें सतर्क

तना छेदक और पत्ती मोड़क कीट की समय पर पहचान कर करें नियंत्रण, अधिक उर्वरक और जलभराव से बचने की सलाह धान की फसल में तना छेदक एवं पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि कीटों के शुरुआती लक्षणों की समय पर पहचान कर उचित नियंत्रण उपाय अपनाने से फसल को होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग तथा लंबे समय तक अधिक जलभराव रहने से इन कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसान संतुलित उर्वरक उपयोग और उचित जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। तना छेदक कीट से फसल को पहुंचता है नुकसान तना छेदक धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में शामिल है। प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप की पहचान करना आसान है। प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पौधे के तने के निचले हिस्से में छोटे–छोटे छेद दिखाई देते हैं तथा मुख्य तना अंदर से खोखला हो जाता है। बालियां सफेद पड़ना गंभीर प्रकोप का संकेत तना छेदक का प्रकोप बढ़ने पर धान की बालियां सफेद होकर पूरी तरह सूख जाती हैं। इससे पौधे में दाने बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए खेत में यदि कुछ पौधों की पत्तियां अचानक पीली पड़ती दिखाई दें या तने में छेद नजर आएं, तो किसान तुरंत फसल का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण उपाय अपनाएं। तना छेदक के नियंत्रण के लिए अनुशंसित छिड़काव कृषि विभाग ने तना छेदक की रोकथाम के लिए क्लोरोसाइपर (क्लोरपाइरीफास 50 प्रतिशत. साइपरमेथ्रिन 5 प्रतिशत) का 50 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है। पत्ती मोड़क कीट की पहचान भी जरूरी धान की फसल में पत्ती मोड़क कीट भी नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे श्सांवा कीटश्च के नाम से भी जाना जाता है। इस कीट की हरी इल्ली धान की पत्तियों को मोड़कर उनके अंदर छिप जाती है और पत्तियों के हरे भाग को खाती है। पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देना प्रमुख लक्षण पत्ती मोड़क कीट के प्रकोप के बाद पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देने लगती हैं। पत्तियों का हरा भाग नष्ट होने से पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता प्रभावित होती है। खेत में ऐसी पत्तियां दिखाई देने पर किसान फसल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण उपाय अपनाएं।

पत्ती मोड़क के नियंत्रण के लिए ये विकल्प कृषि विभाग ने पत्ती मोड़क कीट के नियंत्रण के लिए किसानों को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी का 6 से 10 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर अथवा एमामेक्टिन बेंजोएट 5 प्रतिशत एसजी का 8 से 10 ग्राम प्रति स्प्रेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी है। अधिक उर्वरक और जलभराव से बचें कृषि विभाग के अनुसार खेत में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का उपयोग करने तथा लंबे समय तक अधिक पानी भरा रहने से कीटों के प्रकोप की स्थिति बन सकती है। किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें और खेत में जलभराव की स्थिति न बनने दें। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करने से कीटों की शुरुआती पहचान और समय पर नियंत्रण संभव होगा। समय पर पहचान और नियंत्रण से सुरक्षित रहेगी फसल कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि धान की फसल में कीट प्रकोप के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें। खेतों में नियमित निगरानी रखें और पत्तियों के पीला पड़ने, तने में छेद होने, बालियां सफेद पड़ने अथवा पत्तियों पर सफेद–पारदर्शी धारियां दिखाई देने पर तत्काल उचित नियंत्रण उपाय अपनाएं। समय पर की गई कार्रवाई से फसल को होने वाले नुकसान को कम करने के साथ बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

# जन-विरोधी है केंद्र की चीनी नीति, गरीबों के लिए इसे खरीदना मुश्किल

नीरज

भारत में चीनी की कीमतों में हालिया भारी बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार के बयानों पर एक नजर डालने से ही यह साफ हो जाता है कि केंद्र की चीनी नीति में गंभीर खामियां हैं और यह जन–विरोधी है, जिससे गरीबों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है। साथ ही, कीमतों को नियंत्रित करने में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कीमतों को नियंत्रित करने के सरकारी दावों के बावजूद, 25 अगस्त, 2026 को पूरे भारत में निजी बाजार में खुदरा चीनी की कीमतें 65 रुपए से 80 के बीच पहुंच गईं, जबकि श्प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टमश के आधिकारिक सरकारी आंकड़ों में 24–25 अगस्त को राष्ट्रीय औसत कीमत 63.05 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। 20 जुलाई को कीमत 48.18 प्रति किलोग्राम थी, जहां से इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है।केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कीमतों में इस बढ़ोतरी के लिए श्उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, फसल को नुकसान, वैश्विक आपूर्ति में कमी, त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी हुई मांग, और उद्योग के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरीश को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय ने जो भी कहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा चीनी संकट और कीमतों में भारी बढ़ोतरी के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। 21 अगस्त को ही मंत्रालय ने कहा था कि मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 306लाख टन होने की उम्मीद है, जो अनुमानित 345लाख टन से काफी कम है। मंत्रालय ने जमाखोरी रोकने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की सूची भी दी थी। हालांकि, त्योहारी सीजन से पहले स्थिति और खराब होती जा रही है। दो महीनों में चीनी की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।चीनी उद्योग ने खुद कहा है कि चीनी की कोई वास्तविक भौतिक कमी नहीं है और कीमतों में इस भारी बढ़ोतरी के लिए सट्टेबाजी वाली खरीद और स्टॉक जमा करने को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, लगभग 30 लाख टन चीनी, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है, को एथनॉल उत्पादन के लिए भेज दिया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा संकट सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत में श्चीनी कम हैश, बल्कि यह एक गहरी पॉलिसी से जुड़ी समस्या को दिखाता है। जैसे, सरकार ने एक ही समय में गन्ने की ज्यादा तय कीमतों, एथनॉल के लिए गन्नेध्चीनी के इस्तेमाल, आयात से सुरक्षा और घरेलू चीनी मार्केटिंग पर नियंत्रण जैसी नीतियां अपनाई हैं, जबकि कीमत बढ़ने का बोझ उपभोक्ता को उठाना पड़ता है।सरकार की नीति स्पष्ट रूप से उपभोक्ता–विरोधी है। पहला, क्योंकि सरकार गन्ना उगाने वालों को मिलने वाली कीमत की तो सुरक्षा करती है, लेकिन चीनी उपभोक्ता के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। गन्ने के लिए सरकारी श्फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसश (एफआरपी) 2016–17 में 230 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2025–26 में 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो लगभग 54.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। गलती एफआरपी में नहीं है, क्योंकि किसानों को समर्थन देना सही है। समस्या असंतुलन में हैरू गन्ने की कीमतें प्रशासनिक रूप से ऊपर की ओर सुरक्षित रखी जाती हैं, जबकि गरीब उपभोक्ता को इसके कारण बढ़ी हुई कीमत का सामना बाजार में करना पड़ता है।दूसरा, भारत की एथनॉल नीति ने असल में पेट्रोल और खाने–पीने की चीजों के इस्तेमाल के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। सरकार 20 प्रतिशत एथनॉल मिलावट का अपना मकसद पूरा करने के लिए चीनी मिलों को गन्नाध्चीनी को एथनॉल में बदलने के लिए बढ़ावा दे रही है। इस साल 30 लाख टन चीनी के बराबर मात्रा खाद्य चीनी के बजाय एथनॉल बनाने में इस्तेमाल हुई। साफ तौर पर सरकार ने एथनॉल और चीनी के उत्पादन के बीच कोई संतुलन नहीं बनाया, जिससे मौजूदा संकट में काफी योगदान मिला। सरकार ने अपनी ऊर्जा नीति के मकसद को प्राथमिकता दी और गरीब उपभोक्ता के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज, चीनी, को सस्ता रखने की परवाह नहीं की। तीसरा, आयात से सुरक्षा ने घरेलू कीमतों को तेजी से ठीक स्तर पर लाने को मुश्किल बना दिया है।

भारत आम तौर पर चीनी पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है। केंद्र ने 10 लाख टन बिना आयात शुल्क वाली कच्ची चीनी (रॉ–शुगर) के आयात की इजाजत तभी दी, जब चीनी की कीमतें तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। सरकार ने घरेलू कीमतों को तब सुरक्षित रखा जब चीनी की कीमतें कम थींय उन्होंने आयात को तब आसान बनाया जब उपभोक्ता पहले ही कीमतों में भारी उछाल का झटका झेल चुके हैं। यह सबको अच्छी तरह से पता है कि सरकार देश के चीनी बाजार को नियंत्रित करती है। इसलिए, बाजार गड़बड़ियों के लिए सरकार जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, सरकार उत्पादन, बिक्री, निर्यात, आयात, और यहां तक कि मिलें बाजार में कितनी चीनी जारी कर सकती हैं, इसकी मात्रा को भी विनियमित करती है। यह न्यूनतम बिक्री मूल्य का ढांचा भी बनाए रखती है। इसी माहौल में, कीमतों में भारी बढ़ोतरी का बोझ गरीब उपभोक्ताओं पर बहुत ज्यादा पड़ा है। अमीर परिवारों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ एक परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल चाय, मिठाइयों और त्योहारों के खाने वगैरह में होता है। इसका असर छोटे खाने–पीने का सामान बेचने वालों पर भी पड़ता है। हालांकि भारत सरकार चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से होने वाली मुश्किलों को समझती है, लेकिन उसकी मुख्य चीनी सब्सिडी योजना खास तौर पर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों तक ही सीमित है, जिसके तहत हर परिवार को हर महीने 1 किलो चीनी 18.50 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाती है। इस हिस्से को छोड़कर, सरकार की नीति सभी के लिए चीनी की बाजार की कीमत बढ़ा देती है। मौजूदा संकट सिर्फ एक साल की वजह से नहीं है। चीनी का उत्पादन 2021–22 से लगातार गिर रहा है, जब देश में 359 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि 2023–24 तक यह घटकर सिर्फ 320 लाख टन रह गया। मौजूदा सीजन में इसके सिर्फ 306 लाख टन रहने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने बढ़ते संकट को नजरअंदाज किया और समय पर सही कदम नहीं उठाए। चीनी उद्योग के संगठन ने कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी के लिए श्कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और पहले से भंडारण करनेश को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे बड़ी मात्रा में चीनी बाजार से हट गई और कमी का बनावटी माहौल बन गया।

## संक्षिप्त खबरें

### मानकनगर क्षेत्र में नहर के रेगुलेटर में मिले दो शव, शिनाख्त के प्रयास जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना मानकनगर क्षेत्र के कनौसी पुल के पास नहर के रेगुलेटर में बुधवार सुबह दो शव फंसे होने की सूचना मिली। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नहर से बाहर निकलवाया।पुलिस के अनुसार दोनों शव पुरुषों के हैं। मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया एक मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष तथा दूसरे की उम्र करीब 20 वर्ष प्रतीत हो रही है। करीब 20 वर्षीय युवक के दाहिने हाथ पर 'महाकाल' लिखा हुआ टैटू बना है। पुलिस इसी पहचान चिह्न के आधार पर भी मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।पुलिस ने दोनों शवों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के बाद मोर्चरी भेज दिया है। मृतकों की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ अन्य आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

### गैर जमानती वारंट में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)।अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कमिश्नरेट लखनऊ की कृष्णानगर पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के मामले में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।पुलिस आयुक्त लखनऊ तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर प्रद्युमन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार न्यायालय से वाद संख्या 123047द23, थाना कृष्णानगर, लखनऊ से संबंधित एक गैर जमानती अधिपत्र जारी किया गया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सुनील कुमार पुत्र सोनेलाल, निवासी सैनी निवास, आसाराम बाबू रोड आश्रम, मानसनगर, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### ऑपरेशन डिजिटल कवच' से साइबर ठगों पर शिकंजा, 2.40 करोड़ रुपये की धनराशि होल्ड

लखनऊ, (संवाददाता)।पुलिस आयुक्त के निर्देशन एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में कमिश्नरेट लखनऊ क्राइम ब्रांच द्वारा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के खिलाफ 'ऑपरेशन डिजिटल कवच' चलाया जा रहा है। अभियान के तहत साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही तकनीकी साक्ष्यों, बैंकिंग लेन–देन और धन के प्रवाह का विश्लेषण कर अपराधियों तक पहुंचने के साथ ठगी की धनराशि को तत्काल होल्ड अथवा लियन कराने और पीड़ितों को धनराशि वापस कराने की कार्रवाई की जा रही है।अभियान के तहत 1 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक साइबर सेल द्वारा 2,40,56,807 रुपये की धनराशि होल्ड अथवा लियन कराई गई, जबकि 16,97,462.72 रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए। इसके अतिरिक्त साइबर थाना द्वारा 24 लाख रुपये की धनराशि की वापसी कराई गई।

### रक्षाबंधन पर स्वच्छताकर्मी बहनों ने मंत्री ए.के. शर्मा को बांधी राखी

लखनऊ, (संवाददाता)। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मऊ स्थित टाउन हॉल में स्वच्छताकर्मी महिलाओं ने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को राखी बांधकर भाई–बहन के पवित्र रिश्ते की आत्मीयता को अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर स्वच्छताकर्मी बहनों ने मंत्री के प्रति अपना स्नेह और विश्वास व्यक्त किया।मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी स्वच्छताकर्मी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छताकर्मी बहनें और भाई अपने परिश्रम एवं समर्पण से शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके श्रम और सेवाभाव का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है।उन्होंने स्वच्छताकर्मी महिलाओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में वे उनके साथ खड़े हैं और हरसंभव मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और एक–दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी है।मंत्री ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ही हमारे शहर स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ एवं सुंदर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को धरातल पर साकार करने में स्वच्छताकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर स्वच्छताकर्मी बहनों द्वारा उन्हें राखी बांधना उनके लिए आत्मीय और भावुक क्षण है।

### डीसीएम और पल्सर की आमने–सामने टक्कर में बाइक सवार की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना क्षेत्र में लखनऊ–हरदोई रोड पर मोटी नीम के पहले बुधवार दोपहर करीब एक बजे डीसीएम और पल्सर मोटरसाइकिल की आमने–सामने टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार अकीक अहमद पुत्र मो. अहमद, निवासी ग्राम मऊ, थाना मोहनलालगंज, गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक शैलेष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर जांच के दौरान पता चला कि डीसीएम वाहन संख्या न्च 32 म्छ 9724 और पल्सर मोटरसाइकिल संख्या न्च32 ड॑ 0680 के बीच टक्कर हुई थी।गंभीर रूप से घायल अकीक अहमद को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार अकीक अहमद मोहनलालगंज से मलिहाबाद जा रहे थे। हादसे की सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करा दिया है। डीसीएम चालक की तलाश की जा रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

### 30 मिनट व्यायाम और आठ घंटे की नींद से कम होगा अनियमित माहवारी का खतरा

लखनऊ, (संवाददाता)। महिलाओं और युवतियों में पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीएमओएस) जिसे पीसीओडी भी कहते हैं, सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। माहवारी अनियमितता से कई तरह की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हर छात्रा के लिए रोज 30 मिनट व्यायाम करना जरूरी है और 7–8 घंटे की पर्याप्त नींद अनिवार्य है। इससे पीएमओएस का खतरा काफी कम हो जाता है। ये बातें केजीएमयू के स्त्री रोग विभाग की एडिशनल प्रोफेसर डॉ. मोना असनानी ने कहीं।

## मायावती की अपील - बंद किए गए 30 हजार स्कूलों को दोबारा खोले यूपी सरकार

लखनऊ, (संवाददाता)। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि योगी सरकार की ओर से यूपी के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा एक सही निर्णय है पर ये कदम चुनावी अधिक लगता है। उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलनरत छात्रों की भी सुनने के लिए सरकार से अपील की है। वहीं, प्रदेश में बंद किए गए 30 हजार स्कूलों को खुलवाने की भी अपील की है। 1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले छह महीने में (अर्थात विधानसभा आमचुनाव तक) एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा हालांकि विलम्ब से उठाया गया सही किन्तु चुनावी कदम ज्यादा लगता है फिर भी वे नियुक्तियां पेपरलीक व भ्रष्टाचार आदि के अभिशाप से मुक्त समय से पूरा हो जायें तो यह सही होगा ताकि यह चुनावी छलावा ना साबित हों, जबकि इसके साथ ही एससी, एसटी व ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर भर्तियों के बारे में भी सरकारी घोषणा की लोगों को उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इतना ही नहीं बल्कि यहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के



नियमों को लेकर इन वर्गों के 6,800 अभ्यार्थी अपनी नियुक्ति के लिये भूखे–प्यासे लगातार आन्दोलनरत हैं, उनके बारे में भी सरकार को पूरी सहानुभूतिपूर्वक जरूर सोचना चाहिये, क्योंकि उन्हें वास्तविक राहत सरकार ही दे सकती है। इसके साथ ही, बीएसपी यूपी सहित पूरे देश भर में स्कूली शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को समुचित तौर पर बेहतर बनाने की मांग लगातार करती रहती है किन्तु संभवतः श्जेन–जी' व 'जेन–अल्फा' के दबाव में जो थोड़ी अनचाही हलचल सरकारी स्तर पर देखने को मिल रही है वह मामूली ही सही परन्तु स्कूली शिक्षा में सुधार करने की सही नीयत से हो तो यह उचित होगा और इस क्रम में यहां लगभग 30 हजार जो सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये हैं उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करे तो यह भी जनहित में होगा। इसके अलावा, बुजुर्ग महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा आदि की व्यवस्था से कहीं अधिक महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न आदि से बचाने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भरता के बारे में भी सरकारों को सही नीयत व नीति से कार्य करने की सही नीयत व नीति से कार्य करने की जरूरत है।

## राखी के लिए घड़ियां बन रहीं बहनों की पसंद



लखनऊ, (संवाददाता)। रक्षाबंधन पर परंपरा के साथ आधुनिकता और भविष्य की जरूरतों का भी रंग चढ़ने लगा है। अब भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखियों के साथ घड़ियां भी खूब पसंद की जा रही हैं। कारण ये घड़ियां न सिर्फ कलाइयों को सजाती हैं, बल्कि भाइयों के लिए आगे भविष्य में भी काम आती हैं जबकि राखियां कुछ दिन ही टिकती हैं। हजरतगंज स्थित मल्टीब्रांड स्टोर के प्रतिनिधि प्रियदर्शन निगम बताते हैं कि दो तीन दिनों से 10 हजार तक की रेंज वाली घडियों की बिक्री ज्यादा हुई है। वैसे तो बाजार में सन्नाटा है लेकिन राखी के पर्व की वजह से हल्के रेंज वाली घड़ियों की बिक्री ठीक हुई है। वह बताते हैं कि ऐसी बहनें जो भाइयों के लिए चांदी की राखी खरीदने का शौक रखती हैं, वह अब घड़ियों का रुख कर रही हैं। क्योंकि, चांदी की अच्छी राखी की कीमत 3 से 5 हजार रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसी रेंज में हमारे पास ब्रांडेड और चमचमाती घड़ियां मिल जाती हैं। बताया कि इनकी रेंज 10 हजार तक है। इसमें भी सबसे ज्यादा 4–6 हजार रुपये के बीच की घड़ियां ज्यादा पसंद की गईं। बहनें इस बार चांदी और रुद्राक्ष मिश्रित राखियां भी खरीद रही हैं। चौक के सराफा कारोबारी विनोद माहेश्वरी बताते हैं कि चांदी और रुद्राक्ष का अद्भुत मेल होता है। माना जाता है कि इसे धारण करने वाले को शीतलता मिलती है, मन शांत रहता है। बताया कि बाजार में एक रुद्राक्ष से लेकर 5 रुद्राक्ष के संयोजन की राखियां बिक रही हैं। इनकी कीमत 1500 से लेकर 20 हजार तक है।

## एडेड माध्यमिक विद्यालयों में खत्म होगा प्राधिकारी नियंत्रक का खेल, शासन ने किया जवाब–तलब



लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का चुनाव लटकाकर प्राधिकारी नियंत्रक बने रहने की व्यवस्था पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रबंध समिति के विवाद से जुड़े 36 विद्यालयों के मामलों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब–तलब किया है। साथ ही, इन विद्यालयों में प्रबंध समिति के चुनाव व गठन की अपडेट जानकारी भी मांगी गई है। विभाग के विशेष सचिव संदीप परमार की अध्यक्षता में जुलाई में हुई बैठक में संबंधित विद्यालयों में जल्द प्रबंध समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे। अब शासन ने बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति मांगी है। प्रबंध समिति में विवाद होने पर मामला रजिस्ट्रार, सोसाइटी, चिट्स एंड फंड के समक्ष जाता है। वहां निर्णय लंबित रहने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक या जिला विद्यालय निरीक्षक किसी समूह ख के अधिकारी को प्राधिकारी नियंत्रक नामित कर सकते हैं। कई मामलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक या राजकीय कॉलेज के प्राचार्य को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है। प्राधिकारी नियंत्रक विद्यालय के प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की प्रोन्नति, भवन निर्माण, अवकाश व वेतन समेत खास मामलों में निर्णय लेते हैं। शासन को आशंका है कि कुछ मामलों में प्रबंध समिति का चुनाव अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है। ऐसे में विवादों का निस्तारण कर नई समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। कई स्कूल हैं शामिलरू इन 36 विद्यालयों में लखनऊ के क्वींस एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज और श्री योगेश्वर ऋषिकुल इंटर कॉलेज, रायबरेली का गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज तथा अयोध्या का लाला राम कुमार इंटर कॉलेज समेत उन्नाव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज शामिल हैं।

## किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना काकोरी पुलिस ने किराना दुकान का शटर तोड़कर नकदी और सामान चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी संरक्षण में लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया किराना सामान बरामद किया गया है।पुलिस के अनुसार 13 जुलाई 2026 को राजेन्द्र गुप्ता निवासी सरोसा भरोसा, थाना पारा ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दुकान का शटर तोड़कर करीब 40 हजार रुपये नकद और परचून का सामान चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थीं।25 अगस्त को काकोरी पुलिस घुरघुरी तालाब के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल तीन व्यक्ति चोरी किए गए किराना सामान के साथ असरखेड़ा की ओर से मोहान रोड स्थित एक स्कूल के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दीपांशु पुत्र श्रीराम जी पाण्डेय, निवासी निसारूपुर, थाना इटियाथोक, गोण्डा, हाल निवासी असरखेड़ा, काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष, अनिकेत पुत्र सजीवन पाल, निवासी ईंटगांव, थाना काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष तथा करीब 16 वर्षीय बाल अपचारी को पकड़ लिया।तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार का किराना सामान बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई की रात उन्होंने एक साथ मिलकर पुरैना मोड़, मोहान रोड के पास स्थित किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरी की थी। बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दीपांशु और अनिकेत को रात करीब 9रू42 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पेटी क्लीनिक प्लस शैम्पू, करीब आठ किलोग्राम छोहारा, गोमती मसाला 10 पैकेट, राजश्री मसाला पांच पैकेट, 500 ग्राम दालचीनी, एक किलोग्राम मखाना, एसएनके मसाला 10 पैकेट, स्टार ब्रांड बीड़ी दो पैकेट, डव शैम्पू पांच लड़ी, करीब डेढ़ किलोग्राम काजू, कमलापसंद मसाला पांच पैकेट, सुपरफास्ट तंबाकू पांच पैकेट और करीब दो किलोग्राम धनिया बरामद किया है।

## राखी बांधने गांव पहुंचीं बेटियां, एक माह बाद घर लौटे चेहरे खिले

अयोध्या।करीब एक माह तक प्रशिक्षण केंद्र में रहकर कौशल प्रशिक्षण हासिल कर रहीं ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए रक्षाबंधन का पर्व इस बार खुशियों की सौगात लेकर आया।प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बेटियां अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए गांव पहुंचीं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस यात्रा सुविधा ने उनकी घर वापसी को आसान और सुविधाजनक बना दिया।ये बेटियां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉडर्न बेबी नर्सरी स्कूल समिति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सौजन्य से संचालित किया जा रहा है।करीब एक माह बाद घर लौटने की खुशी बेटियों के चेहरों पर साफ नजर आई।किसी को भाई की कलाई पर राखी बांधने की खुशी थी तो कोई लंबे समय बाद माता–पिता और परिवार से मिलने को लेकर उत्साहित दिखी।प्रशिक्षु बेटियों ने बताया कि रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलने से उन्हें बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सुरक्षित तरीके से अपने गांव पहुंचने में काफी सहूलियत मिली।कौशल के साथ आत्मनिर्भरता की राहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।प्रशिक्षण केंद्र में बेटियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ सुरक्षित आवासीय वातावरण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार हासिल कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

## राष्ट्रीय खेल दिवस पर गनपत सहाय महाविद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में छात्र–छात्राओं ने दिखाया दम



ब्यूरो चीफ .. आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुरः गनपत सहाय महाविद्यालय के पयागीपुर स्थित मुख्य परिसर में मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के अवसर पर शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्रबंधक डॉ. ओमप्रकाश पाण्डेय 'बजरंगी' के मार्गदर्शन में हुआ।कार्यक्रम की शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अंग्रेज सिंह राणा एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.रवींद्र शुक्ल द्वारा मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा एवं महाविद्यालय के संस्थापक बाबू गनपत सहाय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। खेल दिवस के इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया।पूरे परिसर में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दिन भर चलीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में 'रस्सा–कस्सी' (टग ऑफ वार) और '1500 मीटर दौड़' दर्शकों और छात्रों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। 1500 मीटर दौड़ में धावकों ने अपनी सहनशक्ति और गति का बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं रस्सा–कस्सी के मुकाबले में टीमों के बीच जबरदस्त जोर–आजमाइश और टीम वर्क देखने को मिला।मैदान में मौजूद सहपाठियों और शिक्षकों की तालियों एवं नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।इस अवसर पर प्राचार्य प्रो.अंग्रेज सिंह"राणा"ने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को खेल भावना को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी और सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित की ।वरिष्ठ कार्यक्रमाधिकारी डॉ.विष्णु शंकर अग्रहरि ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक सुदृढ़ता, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का भी विकास करते हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन और समापन पर शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शुक्ल ने सभी प्रतिभागी छात्र–छात्राओं, खेल प्रेमियों और महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिताओं के अंत में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को सराहा गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया।इस अवसर पर प्रो.शक्ति सिंह, प्रो.नीलम तिवारी, प्रो.गीता त्रिपाठी,डॉ.अरविंद द्विवेदी, डॉ. विक्रमादित्य, डॉ.किशोर भटनागर, डॉ .विनोद उपाध्याय, डॉ.अवधेश कुमार, डॉ.मनोज उपाध्याय,डॉ. डॉ. दीपा सिंह,डॉ.उर्मिला मिश्रा,डॉ.कुंवर दिनकर प्रताप सिंह एवं अनेकों प्राध्यापकगण,कर्मचारीगण एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

## 'राज्यपाल की अध्यक्षता वाली रेडक्रॉस की बैठक के लिए प्रदेश की नामित सूची में डॉ रवि मोहन व डॉ विजय जौहरी नामित'



'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी उ0प्र0 शाखा की वार्षिक बैठक 31 अगस्त, सोमवार को प्रातः 10 बजे लखनऊ स्थित राजभवन में महामहिम राज्यपाल एवं इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी उ0प्र0 की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित प्रस्तावित है। बैठक में रेडक्रॉस के प्रदेश सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी सहित प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न जनपदों की रेडक्रॉस शाखाओं के पदाधिकारी एवं अधिकारी सहभागिता करेंगे। प्रदेश मुख्यालय द्वारा जारी नामित सूची में जनपद शाहजहांपुर से डॉ रवि मोहन एवं डॉ विजय जौहरी तथा अनुज को राजभवन में प्रस्तावित आयोजित इस बैठक में प्रतिभाग के लिए नामित किया गया है। लखनऊ प्रदेश मुख्यालय द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गए कि जारी सूची में नामित प्रतिनिधि ही बैठक में प्रतिभाग करेंगे, उनके स्थान पर किसी अन्य प्रतिनिधि की सहभागिता नहीं होगी। डॉ रवि मोहन एवं डॉ विजय जौहरी बैठक में जनपद शाहजहांपुर की आवाज को प्रदेश के उच्च स्तर पर रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान एवं ब्लड बैंक की आवश्यकता तथा रेडक्रॉस की संपत्ति के जनहित में उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष रखेंगे। विशेष रूप से पूर्व की भांति जली कोठी के सामने स्थित रेडक्रॉस की संपत्ति, जहां पूर्व में आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित होता था, पर ब्लड बैंक स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए राज्यपाल महोदया एवं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया जाएगा। डॉ विजय जौहरी ने बताया कि डॉ रवि मोहन के परिवार के सभी सदस्य इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य रहे हैं और लंबे समय से रेडक्रॉस की मानवसेवा की भावना से जुड़े हुए हैं। परिवार की यही सेवा परंपरा डॉ रवि मोहन को भी पीड़ित, मानवता की सहायता, स्वास्थ्य सेवा और जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रेरित करती रही है। उन्होंने कहा कि डॉ रवि मोहन जनपद में रेडक्रॉस के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल संस्था की गतिविधियों तक सीमित न रहकर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य एवं मानवीय सहायता पहुंचाना तथा समाज में सेवा भावना को मजबूत करना है। राजभवन की इस बैठक में प्रदेश स्तर की नामित सूची के माध्यम से शाहजहांपुर को प्रतिनिधित्व मिलना जनपद के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जनपद की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सीधे प्रदेश के शीर्ष स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा।

# राखी प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा, विजेताओं को मिले पुरस्कार



अयोध्या (DKU सपअम ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या पब्लिक सेवा संस्थान की ओर से बच्चों में रचनात्मकता, संस्कार और भारतीय पर्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के वीएन अकादमी, टीपी कॉन्वेंट स्कूल और विमला देवी इंटर कॉलेज के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और हुनर का परिचय देते हुए आकर्षक एवं सुंदर राखियां तैयार कीं। बच्चों की प्रतिभा और मेहनत का मूल्यांकन करने के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ–साथ उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करती हैं। संस्था की ओर से सामाजिक, शैक्षिक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों एवं समाज के हित में लगातार किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की गई। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, विमला देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश दुबे, डायरेक्टर राजेश तिवारी समेत विद्यालयों के शिक्षक एवं स्टाफ मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी प्रतिभागी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

# काशीराम कॉलोनी में नशे के खिलाफ गरजा रायगंज चौकी का सिंघम अंदाज, चौकी प्रभारी राणा दिग्विजय सिंह ने दी दो टूक चेतावनी



अयोध्या (DKU live) ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कुमार। अयोध्या कोतवाली अयोध्या क्षेत्र की रायगंज चौकी पुलिस ने काशीराम कॉलोनी में कथित अवैध नशे से जुड़े पदार्थों की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। चौकी प्रभारी राणा दिग्विजय सिंह ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि नशे का अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशीराम कॉलोनी में नशे से संबंधित पदार्थों की बिक्री की शिकायतों को लेकर पुलिस ने निगरानी और कार्रवाई का रुख तेज किया है। चौकी प्रभारी का सख्त संदेश है कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नशे का कारोबार कर रहे हैं, वे संभल जाएं, अन्यथा कानून के शिकंजे के लिए तैयार रहें। राणा दिग्विजय सिंह का अंदाज इस कार्रवाई में पूरी तरह सख्त और एक्शन मोड में नजर आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की नजर इलाके में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस चेतावनी के बाद नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मचने की चर्चा है। वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पुलिस की सख्ती से कॉलोनी में नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा। राणा दिग्विजय सिंह का साफ संदेशकृ "नशे का कारोबार करने वाले संभल जाएं। कानून से खिलवाड़ किया तो कार्रवाई तय है।" रायगंज चौकी प्रभारी का यह सख्त तेवर साफ संकेत दे रहा है कि अयोध्या की सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

# बिना पूरी पड़ताल किये बिना मकान मालिक संदिग्ध लोगो को दे रहे मकान

अयोध्या।शहर में दूर–दराज से आकर किराये के मकानों में रहने वाले संदिग्ध लोगों के सत्यापन को लेकर पुलिस और मकान मालिकों की उदासीनता कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।कई स्थानों पर बिना पूरी जानकारी और पहचान की पड़ताल किए किरायेदारों को मकान दे दिया जाता है।ऐसे में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए तो पुलिस के सामने उसकी पहचान और तलाश करना मुश्किल हो जाता है।कई मकान मालिक किरायेदारों की पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराने में रुचि नहीं दिखाते।वहीं, पुलिस स्तर पर भी किरायेदारों के सत्यापन की नियमित प्रक्रिया हर स्थान पर प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है।जब किसी बड़ी आपराधिक घटना के बाद सामने आता है, जब पुलिस संदिग्ध की तलाश में मकान मालिक तक पहुंचती है।पूछताछ के दौरान कई बार यह सामने आता है कि जिस व्यक्ति को मकान मालिक महीनों से किराये पर रखे हुए था,उसके स्थायी पते, मूल निवास और अन्य जरूरी जानकारियों की भी पूरी जानकारी उसके पास नहीं है।घटना के बाद शुरू होती है संदिग्ध की पहचान और उसके ठिकाने की तलाश, लेकिन तब तक वह शहर छोड़कर दूसरे जिले या प्रदेश तक पहुंच चुका होता है।शहर के कई मोहल्लों, कॉलोनियों, किराये के मकानों के अलावा होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों की जानकारी भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होती है।यदि समय रहते संदिग्ध व्यक्तियों और किरायेदारों का सत्यापन हो तो किसी आपराधिक घटना की स्थिति में पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग आसानी से मिल सकती है।स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब दो दशक पहले चौकी और थाना स्तर पर किरायेदारों के सत्यापन को लेकर पुलिस अधिक सक्रिय रहती थी।बताया कि पहले स्थानीय पुलिस द्वारा समय समय पर प्रत्येक थाना क्षेत्रों में किराये के मकानों और उनमें रहने वाले लोगों की जानकारी अपडेट रखने पर जोर दिया जाता था।स्थानीय पुलिसकर्मी मकान मालिकों से संपर्क कर किरायेदारों का सत्यापन कराने के साथ ही उन्हें इसके महत्व के प्रति जागरूक भी करते थे।इस संबंध में एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि समय–समय पर विभिन्न थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस द्वारा किरायेदारों के सत्यापन कराया जाता है।

# मसौधा चीनी मिल के एसीएम धर्मेंद्र कुमार राव ने चीनी मिल के सोहावल सुपरवाइजर संजय चौबे के साथ गन्ना बंधाई कार्य का किया जायजा



(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मसौधा चीनी मिल के ए सी एम धर्मेंद्र कुमार राव ने चीनी मिल के सोहावल सुपरवाइजर संजय चौबे के साथ क्षेत्र के कई गांवों में गन्ना किसानों से किसानों के खेतों में जाकर मुलाकात किया।इस अवसर पर ए सी एम धर्मेंद्र कुमार राव और चीनी मिल के गन्ना सुपरवाइजर संजय चौबे ने मसौधा चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के हितों के लिए की जा रही विविध जानकारी के बारे में किसानों को बताया।उन्होंने इस अवसर पर मौजूद सभी किसानों को अक्तूबर माह में आटम बोआई करने की सलाह दिया।इस अवसर पर उन्होंने किसानों को सलाह दिया कि सभी किसान अक्टूबर माह में गन्ना की प्रजातियों जिसमें प्रमुख रूप से सीओएलके 14201,सीओ 20016 , सीओ 21012 , सीओ 0118 आदि की बोआई करके सहफसली के रूप में चना , मटर, सरसों आदि की बोआई करके मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।इस दौरान मसौधा चीनी मिल के एसीएम धर्मेंद्र कुमार राव और चीनी मिल के सोहावल गन्ना सुपरवाइजर संजय चौबे ने मसौधा चीनी मिल सोहावल क्षेत्र अंतर्गत उचितपुर गांव में गन्ना किसान डब्बू वर्मा और इब्राहिमपुर गांव के गन्ना किसान शिव वरदान तिवारी के गन्ना के खेतों में जाकर गन्ना की खेती और गन्ना की बंधाई कार्य का जायजा लिया और मौजूद किसानों को गन्ना की खेती करने के लिए अधिकाधिक रूप से जागरूक किया ।

# कंदेला गांव में राम लगन मौर्य हत्याकांड में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार

मसौदा,अयोध्या।शनिवार को पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कंदेला गांव में हुए 25 अगस्त को हुए रामलगन मौर्या हत्याकांड में पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है।जिनको गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया जहां अदालत ने जेल भेज दिया।शनिवार को स्वाट, सर्विलांस और पूराकलंदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पूराकालंदर थाना क्षेत्र के वर्क शॉप के पास मुखबिर की सूचना पर भाग रहे सचिन उपाध्याय निवासी प्रतापगढ़ और प्रांजल सिंह निवासी अमेठी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों के कब्जे से 0.32 बोर की पिस्टल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 25 अगस्त की शाम हुई गोली चलने एवं बमबाजी में रामलगन मौर्या पुत्र संतराम की गोली लगने से मौत हुई थी,जबकि उनकी मां पार्वती देवी गंभीर रूप से घायल हैं और केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ में उपचाराधीन हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस संबंध मे थाना प्रभारी पूराकलंदर अश्वनी पांडेय ने बताया प्रकाश में आए 2 आरोपी सचिन उपाध्याय एवं प्रांजल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की राह दिखाई जाएगी।




# काशीराम कॉलोनी में नशे के खिलाफ शीघ्र ही अभियान चलायेगी रायगंज पुलिस

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।कोतवाली अयोध्या क्षेत्र की रायगंज चौकी पुलिस ने काशीराम कॉलोनी में कथित अवैध नशे से जुड़े पदार्थों की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है।यह बाते चौकी प्रभारी रायगंज राणा दिग्विजय सिंह ने बताई। बताया कि नशे का अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नशे का कारोबार कर रहे हैं कि पुलिस की नजर इलाके में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

# अमेठी में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत, हॉस्टल में लटका मिला शव बल्दीराय के सादुल्लापुर गांव की निवासिनी है छात्रा

ब्यूरो चीफ .. आलोक कुमार श्रीवास्तव

अमेठी/सुल्तानपुर । जनपद अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा दीप्ति यादव (उम्र 22 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका दीप्ति यादव पुत्री कुंवर बक्श यादव, निवासी ग्राम– सदुल्लापुर, थाना– बल्दीराय, जनपद– सुल्तानपुर की रहने वाली थी। वह मुंशीगंज नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। माँ सुनीता की तहरीर के अनुसार, 28/08/26 को सुबह 11 बजे तक बेटी से उनकी बात हुई थी। उसके बाद दोपहर 1:06 बजे वार्डन नेहा शुक्ला ने फोन कर बताया कि बेटी हॉस्पिटल में है और जल्दी आने को कहा। परिजन जब पहुंचे तो वार्डन ने बताया कि दीप्ति ने फांसी लगा ली है और बंद दरवाजा तोड़कर शव निकाला गया। परिजनों का कहना है कि मौके पर कमरे का दरवाजा और सिटकिनी टूटी हुई नहीं थी, जिससे वार्डन का बयान संदिग्ध लगता है। आरोप है कि प्रधानाचार्य डॉ. एस. पी. सिंह और वार्डन ने बिना परिजनों को शव दिखाए और बिना पंचनामा के ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने थानाध्यक्ष मुंशीगंज, अमेठी से संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच और हॉस्टल के CCTV फुटेज सुरक्षित करने की मांग की है।

# अयोध्या में 18 करोड़ से बनेगा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कांप्लेक्स



(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।रामनगरी में खिलाड़ियों को आधुनिक एवं विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है।वशिष्ठ कुंड वार्ड में 17 करोड़ 83 लाख 81 हजार रुपये की लागत से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा।करीब 4684 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनने वाले इस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शनिवार को खेल दिवस के अवसर पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने वैदिक विधि–विधान से भूमि पूजन कर स्टेडियम का शिलान्यास किया।इस अवसर पर महापौर ने कहा कि योगी सरकार में खेल सुविधाओं के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। अयोध्या में आधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनने से शहर के खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और नई प्रतिभाएं उभरकर सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि कक्षा से अधिक व्यावहारिक ज्ञान खेल के मैदान में मिलता है। खेल व्यक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती और खेल दिवस पर खिलाड़ियों के लिए इससे बड़ी सौगात और कुछ नहीं हो सकती। यह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स अयोध्या के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगा।कार्यक्रम का संचालन अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ ने किया।इस मौके पर नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत बनने वाला स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 4684 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इसमें भवन का निर्माण 3064 वर्ग मीटर में होगा। भवन में 1372 वर्ग मीटर का बेसमेंट, 1664 वर्ग मीटर का भूतल तथा करीब 789 वर्ग मीटर में प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण होगा।करीब 91 वर्ग मीटर का टेरेस भी विकसित किया जाएगा।स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती कोर्ट, जिम्नेशियम, टेबल टेनिस हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, कैफेटेरिया एवं किचन, कोच रूम, कार्यालय, शौचालय, लिफ्ट और सीढ़ियों की सुविधा होगी। परिसर में पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी, जहां चार पहिया और दोपहिया वाहन खड़े किए जा सके।कार्यक्रम के दौरान खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाली 10 खेल प्रतिभाओं एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया।इनमें बास्केटबॉल कोच चंदेश्वर पांडेय, वॉलीबॉल के शिवेंद्र सिंह एवं अनुज मिश्रा, कबड्डी के मुकेश निषाद, एथलेटिक्स के गोलू मौर्य, क्रिकेट के रंगेशमणि त्रिपाठी, बैडमिंटन के अनूप दुबे, हॉकी के राजेश श्रीवास्तव, वॉलीबॉल के सालिकराम यादव और एथलेटिक्स की नीतू गुप्ता शामिल रहीं।

इसके अलावा वशिष्ठ फाउंडेशन की ओर से साइकिलिंग के क्षेत्र में प्रतिभा दिखा रही 15 वर्षीय किशोरी बेबी को स्वर्गीय अमित सिंह अश्मित सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान स्वरूप फाउंडेशन की ओर से उसे 11 हजार रुपये का चेक दिया गया।इस मौके पर उपसभापति संतोष सिंह, पार्षद रंजना यादव, विनय जायसवाल, रमाशंकर निषाद, सूर्यकुमार तिवारी, चंदन सिंह, हरिश्चंद्र गुप्ता, अभिनव पांडेय, अजय पांडेय, ज्ञान केसरवानी, सुशील मिश्र बबलू, दीप कुमार, सुल्तान अंसारी, सुफियान, भाजपा नेता हेमंत जायसवाल, आलोक द्विवेदी, रवि सोनकर, दिव्य प्रकाश तिवारी, इंजीनियर रवि तिवारी, मधुकरिया संत एमबी दास, धर्मेंद्र सिंह, व्यापारी नेता अंजनी गर्ग, खेल जगत के रोहित शर्मा, राहुल सिंह, योगेश्वर सिंह, सुनील अवस्थी, श्रीनिवास शास्त्री,अजीत सिंह, क्रीड़ा अधिकारी अमित सक्सेना आदि मौजूद रहे।

# पांच माह से नहीं हो रहा है मानदेय का भुगतान,शिक्षक संघ पान्डेय गुट ने उठायी मांग

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पाण्डेय गुट के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जनपद अयोध्या के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का माह अप्रैल से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है।वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मानदेय भुगतान हेतु शासन से धान आवंटन प्राप्त हो चुका है लेकिन शिक्षा विभाग की शिथिलता के कारण आज तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानदेय के भुगतान से वंचित हैं जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि मानदेय का भुगतान न होने के कारण उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानसिक और आर्थिक पीड़ा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय से किया जाए लेकिन कल रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर भी उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानदेय भुगतान का इंतजार कर रहें हैं।जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कल ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त शिक्षक निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अयोध्या से शीघ्र अति शीघ्र मानदेय भुगतान करने की मांग की है।

पत्रावली संख्या -1-7520, पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या - 405/1956-57

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ

वीरेन्द्र बहादुर सिंह
प्रदेश मंत्री

निवास : 1/13/16E, खपराडीह कोठी कैम्पस, सिविल लाइन्स - अयोध्या

|| वयम् राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः ||

सेवा में,
1.संयुक्त शिक्षा निदेशक,अयोध्या मण्डल अयोध्या।
2.जिला विद्यालय निरीक्षक,अयोध्या।
3.वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या।

भवदीय
वीरेन्द्र बहादुर सिंह

# बीकापुर तहसील परिसर मे स्थित चकबंदी न्यायालय जर्जरावस्था मे तब्दील,रहता है हमेशा खतरा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिले के बीकापुर तहसील में खुला चकबंदी कार्यालय जर्जर होने के साथ ही उसकी छते बरसात में टपक रही हैं। वहां काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे हैं।कई बार कर्मचारियों ने अपने निजी पैसे से थोड़ी बहुत मरम्मत भी करवाई है।लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है।अलमारी में पत्रावलियां भी है जिसे बचाने के लिए उसके ऊपर से कर्मचारियों ने पॉलिथीन लगवाया है।इसी तरीके से सीओ ऑफिस का जो चौंबर है वहां भी कंप्यूटर पन्नी से ढका गया है सीओ न्यायालय की छत छू रही है खिड़किया खुली है खिड़की में एक भी शीशा नहीं है । जंगली जीव जंतु अंदर प्रवेश कर सकते हैं।यहां पर जो आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जान जाने का खतरा प्रायः बना रहता है।मामले में पता चला है कि सीओ चकबंदी ने जिला अधिकारी और डीडीसी को पत्र भेजा है कि जर्जर कार्यालय के अतिरिक्त उन्हें कोई कार्यालय प्रदान किया जाए लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है।



# मोतिगरपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग

ब्यूरो चीफ .. आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर। मोतिगरपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग,तीन गोलियां लगीं।मोतिगरपुर के ढेमा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 40 वर्षीय विपिन सिंह पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।सीने में तीन गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए।जिला मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।पुलिस ने शिवम सिंह समेत दो अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।एसओजी समेत तीन टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं।घटनास्थल से चार खोखे बरामद हुए हैं।

# सर्पदंश की शिकार किशोरी की 12 दिन बाद मौत

भदोही, (संवाददाता)। मिश्रधाप गांव निवासी संजय प्रजापति ने बताया कि बेटी सरस्वती (12) बीते 14 अगस्त की रात दो बजे घर में चारपाई पर सोई हुई थी। इसी दौरान घर में छिपा विषैला सर्प ने चारपाई पर पहुंचकर सरस्वती को डस लिया। नींद खुलते ही किशोरी ने सांप को देखा और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर माता–पिता जग गए। सांप को एक डिब्बे में रखकर चिकित्सक को दिखाया। परिजन किशोरी को लेकर मिर्जापुर मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन वाराणसी ले जा रहे थे,।

# अयोध्या को बिजली कटौती मुक्त करने की घोषणा हो रही हवा हवाई साबित - चेतनरायण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।भाजपा सरकार की हर घोषणा की तरह जनपद अयोध्या को बिजली कटौती मुक्त करने की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है।यह आरोप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह,पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंहएवं जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने प्रदेश सरकार पर लगाया है।कांग्रेस नेताओं ने कहा रात हो या दिन कब बिजली चली जाए और कितनी देर के लिए, कुछ पता नहीं व्यापारी और किसान परेशान है छात्रों की पढ़ाई में बाधा पड़ रही है।बिजली ऑफिस पर जनता के फोन को उठाने वाला कोई नहीं है कोई संतोष जनक जवाब बिजली के आने और जाने का नहीं मिलता है, इस भीषण गर्मी में बिजली की असमय कटौती से लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं भाजपा सरकार में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है और बिजली बिल में कोई कमी नहीं है,कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग करती है।जिससे आम नगरियों को राहत मिल सके, जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह,जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने जिला प्रशासन को चेतावनी दिया है अगर एक सप्ताह के अंदर विद्युत व्यवस्था को कटौती से मुक्त नहीं किया जाता और सुचारू रूप से विद्युत ववस्था बहाल नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी विद्युत विभाग का घेराव करेगी।जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन की होगी।



सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।